



रणधीर कुमार

विद्यालय शिक्षक की स्थिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार), भारत

Received-14.07.2023, Revised-20.07.2023, Accepted-25.07.2023 E-mail: aaryavart2013@gmail.com

सारांश: शिक्षा देने वाले को शिक्षक (अध्यापक) कहते हैं। शिक्षिका (अध्यापिका) शब्द शिक्षक (अध्यापक) का स्त्रीलिंग स्वरूप है। यह एक ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है, जो आपको सिखाता है और आपको जीवन की वास्तविक समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाता है। यह दुनिया भर में सम्मानित नौकरियों में से एक है। भारत में शिक्षक दिवस 1962 से डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे 1994 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था।

कुंजीशब्द— पूर्वाचार्य, कर व्यवस्था, राजस्व कोश, वस्तु एवं सेवा, कर, गंतव्य आधारित, मूल्य संवर्धन, नववर्धित मूल्य।

भारत में शिक्षक के लिए गुरु शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल से होता आया है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण यौनि जो हमें जीवन की संपूर्णता को हासिल करने की दिशा में बढ़ने के लिए हमारा पथ आलोकित करता है।

शिक्षक का अर्थ—

शि - शिखर तक ले जानेवाला।

क्ष - क्षमा की भावना रखनेवाला।

क - कमजोरी दूर करनेवाला।

“जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी कमजोरी दूर कर उसको शिखर (सफलता) तक ले जानेवाला ही सच्चा शिक्षक कहलाता है।”

शिक्षक शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द टीचर का हिन्दी अनुवाद है। टीचर के अर्थ निम्नरूपों में लिख सकते हैं—

- * Teacher- Talented, Educated, Adorable Charming Helpful, Encouraging, Responsible.
- * Teacher - Talented, Educated, Attitude Charater, Harmony, efficient, Reliable.
- * Teacher- Trained/ Time Punctual , Efficient able, Cheerfulness, Humble/Honest, Enthusiastic, Resourceful.
- * Teacher- Truthful, Exemplary, Able, Creative, Helpful, Encouraging, Role-model.
- * Teacher- Tactfulness, Entusiastic, Ability Character, Honesty, Efficiency, Resourcefulness.

21 वीं सदी में शिक्षा अनेकानेक बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसी क्रम में शिक्षकों की स्थिति में लगभग दो-तीन दशक से काफी उतार-चढ़ाव आये हैं। इसी उतार-चढ़ाव के कारण इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ जिसके कारण इस विषय पर अपना मंतव्य रखने की कोशिश किया है।

उद्देश्य कथन :-

(क) वर्तमान समय में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सरकारी कर्मचारी के रूप में देखती है। शिक्षकों को इस रूप में नहीं देखा जाता जो बच्चों को शिक्षित करने और उनकी देखभाल करने में लगे हो।

(ख) शिक्षकों को पेशेवर पहचान बढ़ाने और काम करने के हालातों की बेहतरी के उद्देश्य पर आधारित मिश्रित रणनीतियों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ लोगों को शिक्षण के पेशे की ओर आकर्षित करना और वेतन की व्यवस्था ठीक करना।

(ग) विद्यालयों का वातावरण और संस्कृतियों में अधिकाधिक परिवर्तन कर शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाकर शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से करने में सक्षम हो सके।

वर्तमान समय में शिक्षकों की समस्याएँ या स्थिति :-

वर्तमान समय में शिक्षकों की स्थिति बहुत हद तक अच्छी नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के काम करने के स्थिति पर विस्तृत रूप से शिक्षकों और प्रशासकों से बात की गई। बात करने के उपरांत यह बात सामने आई कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में देखती है। जिनकी प्राथमिक निष्ठा प्रशासन के प्रति है। उन्हें एक ऐसे शिक्षक के रूप में नहीं देखा जाता जो बच्चों को शिक्षित करने और उनकी देखभाल करने में लगे हो। समाज में पहले जो अद्वितीय स्थान शिक्षक का था। वह धीरे-धीरे घटता जा रहा है और देश भर के शिक्षक भी आपको यही बताएँगे कि उनकी पेशेवर पहचान कहीं खो गई है।

शिक्षकों की जिस तरह से नियुक्ति की जाती है उनका तबादला किया जाता है उसकी वजह से वे प्रशासन या राजनेताओं के बदलते हुए व्यवहार की चपेट में आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षकों की स्वायत्तता हो गई है और अपने प्रशासन के अधिकारियों को खुश करने में लगे रहते हैं जो कि एक दुखद बात है।

शिक्षकों की कमी भी आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी की वजह से भी शिक्षक समाज में बदलती भूमिका को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के लगभग 42 प्रतिशत स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए केवल एक या दो शिक्षक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नीति निर्देशों के बावजूद भी ये शिक्षक प्रभावी रूप से बहु-कक्षा शिक्षण करने के तरीकों से लैस नहीं है। NCF 2005 का सुझाव है कि बहु-कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षकों को नियोजन करना चाहिए, लेकिन शिक्षक-दिशा की प्रक्रिया अभी भी बहु-कक्षा की स्थिति को असंगत मानती है।



हमारे शिक्षा विभागों में ज्यादातर अध्यापक शैक्षणिक योग्यता, रुचि एवं अभिवृत्ति तथा अनुभव की दृष्टि से अनुपयुक्त है। इसके फलस्वरूप अध्यापक शिक्षा संबंधी कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न नहीं किया जाता है एवं सिर्फ उनकी खाना-पूर्ति ही की जाती है। अतः इस समस्या का निराकरण करना जरूरी है।

प्रधान अध्यापक और शिक्षकों की टीम को इस बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता कि उनके स्कूल में कैसे नियुक्ति किया जाना चाहिए। कई राज्यों में शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है कि जब उन्हें गणित के शिक्षक की जरूरत होती है तब उन्हें भाषा का शिक्षक दे दिया जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे सारे विषय पढ़ाएँ। किसी भी प्रकार के निर्णय में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता बस आदेश दे दिया जाता है और अपनी झूठी करने को कहा जाता है।

शिक्षकों के स्थिति पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव- शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक बाद देश में नई शिक्षा को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1886 ई0 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। परंतु यह शिक्षा नीति पूरी तरह जमीन पर कार्य नहीं कर पायी। अतः इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे। तब अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार हो अब हम लोगों के बीच आई है।

यह शिक्षा नीति शिक्षकों की स्थिति एवं उनके विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारे देश में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखती है। भारत में सबसे अच्छे और विद्वान लोग ही शिक्षक समाज से जुड़ते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमारे शिक्षक समाज के लिए नया स्वरूप लेकर आया है। अभी के समय में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत हद तक मदद कर सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र के अच्छे विद्यार्थी को शिक्षण पेशे में प्रवेश कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत 4 वर्षीय बी0एड0 कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेधा आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों (विशेषकर छात्राओं) के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आस-पास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि की जाएगी।

शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सकें। इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हॉनिकारक प्रक्रिया पर रोक लगायी जाएगी है। राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में ऑनलाइन सॉटवेयर आधारित स्थानांतरण की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) सामग्री और शिक्षण शास्त्र दोनों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तर (बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक) के शिक्षकों को टी0ई0टी0 परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। शिक्षक के शिक्षण के प्रति झुकाव को जानने के लिए कक्षा-कक्ष प्रदर्शन भी करना होगा। इसके साथ-साथ सभी निजी विद्यालयों में भी टी0ई0टी0 पास एवं कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना होगा।

सेवाकाल के दौरान शिक्षकों को स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें। जिनका एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं।

इन कार्यों को सही दिशा देने के लिए स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य-स्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। अतः स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल एवं मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र (दिव्यांग बच्चों सहित) एक सुरक्षित समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें।

शिक्षकों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा कर सकते हैं। शिक्षकों का ज्यादातर समय गैर-शिक्षण गतिविधियों करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से संबंधित नहीं हैं उनको करने की अनुमति नहीं होगी।

शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्ता दी जाएगी। जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो। शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिये जाएँगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। सतत



व्यावसायिक विकास के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के रचनात्मक और अनुकूल आकलन योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षणशास्त्र जैसे अनुभववात्मक शिक्षण कला—एकीकृत, खेल—एकीकृत और कहानी— आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप में शिक्षक को अपने में समाहित करना है।

स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप/मैनेजमेंट कार्यशालाएँ और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे ताकि वे अपनी सर्वोत्तम प्रेक्टिस को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इन संस्था प्रमुख से भी यह अपेक्षित है कि वे भी प्रति वर्ष 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे कि सभी शिक्षकों को बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा। जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगा।

शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ—साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा को धीरे—धीरे वर्ष—2030 तक बहु विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। सभी कॉलेज और विश्व विद्यालय बहुविषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बी0एड0, एम0 एड0 और पीएच0डी0 की डिग्री प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त व्याख्याओं पर विचार करके शिक्षा व्यवस्था तो उत्कृष्ट हो सकती है लेकिन इसे व्यावहारिक एवं वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर लागू करने की व्यवस्था पर विशेष बल देने की जरूरत है। तभी नयी शिक्षा नीति 2020 अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम हो पाएगा। क्योंकि बीते समय में बहुत सारे शिक्षा आयोग एवं शिक्षा नीतियों के असफल होने का कारण सिर्फ शिक्षा नीति में त्रुटि या दोष नहीं है बल्कि सामाजिक स्तर पर उसके समायोजन एवं जमीनी स्तर पर उसे लागू करने में आने वाली समस्याएँ उसकी असफलता के प्रमुख कारणों में से एक रही। अतः यह कहना न्यायसंगत होगा कि नयी शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण जमीनी स्तर पर लागू हो जाने पर शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की संभावना निहित है एवं नयी शिक्षा नीति 2020 अपने संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सक्षम हो पाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Naveen Dsouza - By Google
2. Kailash Meena -In other education , 29-08-2021
3. Open Naukari - 2 Years Ago
4. Vimla Ram Chandran, T. Beteille, S.Goyal, S.Day & P.G. Chaitarjee-Learning Curve-2016
5. डॉ० गिरिश पचौरी, रितु पचौरी – उभरते भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
